आसमान छूती महंगाई : लोगों का बुरा हाल

जीवित रहने के लिए जरूरी अनाज़ एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई दिन-रात लगातार इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि लोग़ों की समझ में यह नहीं आ रहा कि वे क्या करें। दूसरी तरफ, सरकार इस महंगाई को काबू कर पाने की कोई योजना नहीं बना रही है। हां, खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने का प्रस्ताव जरूर करने जा रही है जिसके लिए मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, सरकार ने ग़रीबी रेखा से ऊपर के लोग़ों के लिए सरकारी दुकानों से मिलने वाले राशन की मात्रा घटाने की सिफ़ारिश भी की है। इसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ग़रीबों के लिए तीन रुपये किलो की दर से प्रतिमाह 25 किलो अनाज़ उपलब्ध कराने का जो वायदा किया था, उसे भी क्रियान्वित करने के लिए उपाय करने की योजना है। देश के खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार ने यह कहा है कि ऐसा करने के लिए जो प्रक्रिया चलनी है, उसमें करीब एक साल का समय लग जायेगा। यानी भूख से व्याकुल हो रहे लोग़ों को अभी सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। आने वाले एक साल के अंतराल के बाद क्या कुछ होना है, उसके बारे में जनता क्या सोचती है, वह तो बाद का सवाल है, ग़रीबी की मार से त्रस्त लोग़ों को तो फ़िलहाल कोई सहायता चाहिए। लेकिन क्या सरकार उन्हें कोई राहत दे सकती है? हर्गिज नहीं। अगर सरकार आम जनता की इतनी ही हितैषी होती तो महंगाई की यह मार लोग़ों को झेलनी ही नहीं पड़ती। महंगाई के आसमान छूने का मतलब यही है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों, काला बाज़ारियों और उन विदेशी कंपनियों के हाथों में खेल रही है जिनका एक मात्र काम जनता को लूटना ही है। जो लोग़ वर्तमान सत्ताधारियों की नीयत और मंशा को भलीभांति देख रहे हैं, उन्हें आसानी से यह समझ में आ रहा है कि वर्तमान महंगाई सरकार की लुटेरी नीतियों का परिणाम है। सरकारी आंकड़े ही इस बात के गवाह हैं कि देश में सकल कृषि उत्पाद कितना हुआ और किस तरह बिचौलियों और सट्टेबाजों ने उसे लूटा और अभी भी लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।

सरकारी आंकड़ों से यह साफ़ दिखाई पड़ रहा है कि गन्ने की फसल बंपर होने के बावजूद चीनी किस तरह महंगे से महंगे दर पर बेची जा रही है और गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों ने इस हद तक शोषण किया है कि वे कह रहे हैं कि गन्ने की फ़सल का ज्यादा होना ही उनके लिए परेशानी पैदा करने वाला हो गया। मिल मालिक गन्ना उठाने के नाम पर न सिर्फ़ नखरे दिखाते हैं, बल्कि उनसे बहुत ही कम कीमत पर गन्ने उठा लेते हैं और अपना उत्पाद दबा कर अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। अब जबकि चीनी के आयात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जा रहा है, फ़िर भी चीनी का बाज़ार भाव 40 रुपये से कम नहीं है और न ही इस बात की कोई संभावना है कि भाव कम होंगे। भारतीय बाज़ार मे जिस चीज का भाव बढ़ जाता है, वह फ़िर कभी कमता नहीं है, भले ही सरकार इसके लिये कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। आज महंगाई की जो स्थिति है, वह वर्तमान सरकार के जानबूझ कर किये गये कुप्रबंधन का परिणाम है, न कि बाज़ार की ताकतों के।

चीनी उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि देश के कृषि और खाद्यान मंत्री शरद पवार की काफ़ी पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है, इसलिए अपने हित में वे गन्ना किसानों, विशेष कर गैर महाराष्ट्रीय किसानों की दुर्दशा को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यद्यपि लोग़ इसे मानें या नहीं, पर यह सच है कि भारत का कृषि और खाद्य मंत्री एक चीनी माफ़िया भी है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले यह मंत्री पहले दौर में कृषि मंत्री कम, क्रिकेट मंत्री ज्यादा बना रहा और क्रिकेट उद्योग से इसने इतनी कमाई की कि सामान्य लोग़ इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यही व्यक्ति जब दूसरे दौर में कृषि एवं खाद्य मंत्री बना तो यह कृषि एवं खाद्यान्न क्षेत्र को लूटने में लग गया। इसकी यह लूट तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती थी जब तक यह खाद्य क्षेत्र को विदेशी व्यापारियों के लिए खुला नहीं छोड़ देता। अपने विदेशी आकाओं के भरोसेमंद होने के कारण इसे दुबारा कृषि मंत्री बनाया गया ताकि उत्पादन के इस मूलभूत क्षेत्र में जबरदस्त डाका डाले और विदेशी आकाओं को खुश रख सके। यह काम यह बराबर करता चला जा रहा है जिसका परिणाम है दालों और चीनी आदि के आयात में हर तरह की छूट देना। इससे जहां व्यक्तिगत तौर पर इसे व्यावसायिक लाभ है, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी इसे लाभ ही लाभ है, वह इस रूप में साम्राज्यवादी आका इसके पक्ष में रहें और इसकी 'बहुमूल्य सेवाओं' के बदले राजसत्ता में टिकाऊ स्थान दिलाते रहें। अब यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि स्टॉक में कम चीनी का जो शोर-शराबा इसने गत वर्ष उठाया था, वह झूठा था। पर इसके द्वारा उठाये गये शोर-शराबे का पूरा लाभ चीनी मिलों ने उठाया और विदेशी व्यापारियों को भी इससे लाभ हुआ, वहीं गन्ना उत्पादकों की हालत बिगड़ गई। अब भी उनकी हालत में सुधार का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। अब यह राज्यों पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने गन्ना उत्पादन की वास्तविक हालत सरकार को बतायी ही नहीं। अगर राज्य सरकारों को ही सबकुछ करना हो तो फ़िर इनकी जरूरत ही क्या है?

तर्क देने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि किसान फ़सल पर जहां बाहर से कीटनाशकों का स्प्रे करता है, वहीं बीटी बैंगन में इस स्प्रे में एक हजार गुना ज्यादा मात्रा में कीटनाशक मौजूद होंगे और फ़सल तैयार होने के बाद जब वे बाज़ार में बिकने आएंगे तो बैंगन की भीतर संरचना में जहरीले रासायनिक तत्वों की काफी मात्रा में मौजूदगी बनी रहेगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के गुर्दे, लीवर और रक्त-प्रवाह पर होगा। चूहों पर यह प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने इन तथ्यों को भली-भांति समझ लिया है।

यहां सवाल सिर्फ़ चीनी का ही नहीं है। चावल, गेहूं और दूध के बारे में भी यही हाल है। लोग़ इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जब सरकारी गोदाम गेहूं से भरे हुये थे, शरद पवार ने गेहूं की कमी का ऐसा हौव्वा खड़ा किया कि पूछें मत। इनके शोर-शराबे को देख कर निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किसानों से बहुत सारा गेहूं खरीद लिया और सरकार ने गेहूं का बफर स्टॉक होते हुए भी आस्ट्रेलिया से सड़े गेहूं का आयात किया जो जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। इस तरह सरकार ने अनाज़ के उन व्यापारियों के हित में काम किया जो काले बाज़ार में अपना धंधा खूब तेज़ी से फैलाते हैं और कीमतों को आसमान तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से वे उपभोक्ताओं की जेब में पड़ा एक-एक पैसा तक लूट लेते हैं। ऐसे लुटेरों को सहयोग और समर्थन देने के कारण महंगाई की यह दशा हुई है जिसके कारण अब सामान्य उपभोक्ता कराह रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यही नहीं, इसने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में कटौती कर किसानों के खिलाफ़ ही कदम उठाया है। दूसरी तरफ, जीन संवर्द्धित बीजों को लगाने की पैरवी करते हुए किसानों को लूटने की मंशा दिखलाई है। जिस वायदा कारोबार पर रोक लगाने की मांग जनहितैषी संगठन उठाते रहे हैं, उसे दरकिनार कर, इसने वायदा कारोबार को और भी ज़्यादा फैलाने का काम किया है। जहां तक इस कारोबार का सवाल है, इसकी जड़ें इतनी गहरी होती चली जा रही हैं कि कोई भी राजनेता चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हा, इसके पक्ष में ही बोलता नज़र आता है। अगर कोई खुल कर इसके समर्थन में नहीं आता है तो मौन रह कर ही समर्थन करता है।

इन स्थितियों को देखते हुए यह साफ़ है कि महंगाई में किसी तरह की कमी संभव नहीं है। इस व्यवस्था में महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती ही जायेगी और किसान-मज़दूर एवं आम लोग़ इसके शिकार होते रहेंगे। होते हैं तो हुआ करें, मरते हैं तो मरा करें, आखिर इसकी परवाह ही किसी को क्यों हो।

- प्रतिनिधि

भ्रष्टाचार के लिए कौन है जिम्मेदार?

हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में काफी ऊंचा स्थान रखता है। पूरी दुनिया में मात्र कुछ ही ऐसे देश होंगे जो इससे आगे हों। हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार को ही माना जा रहा है। अधिकांश लोग़ यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। यह कहा जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाये तो देश का काया-कल्प हो जायेगा। सिर्फ़ भ्रष्टाचार के कारण ही देश गर्त में चला जा रहा है। सरकार भी इस बात को मानती है कि देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये विशेष विभाग बना रखें है जिनका एकमात्र कार्य भ्रष्टाचार को रोकना और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाना है। पर सरकार जहां भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, वहीं यह समस्या और बढ़ती ही चली जा रही है। सरकारी अफसरों की छोड़ भी दें तो नेता और बड़े-बड़े मंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जा रहे हैं। लगभग सभी पार्टियों में ऐसे नेता काफ़ी संख्या में हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ऐसे-ऐसे रिश्वतखोर उच्चाधिकारी हैं जिनके घर से करोड़ों की नकदी ही नहीं, नोट गिनने वाली मशीन तक बरामद हो रही है। यह देख कर लोग़ कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कायम रहा तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। सरकार भी आखिर क्या करे? वह तो विकास की एक से बढ़ कर एक योजनायें बनाती है, पर भ्रष्टाचारियों के कारण जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। एक समय स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर बैठ कर राजीव गांधी तक ने कहा था कि विकास के लिए सरकार जो धन खर्च करती है, उसमें रुपये में दस पैसा ही जनता तक पहुंच पाता है और यही बात अब उनके पुत्र एवं युवराज राहुल गांधी भी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भ्रष्टाचार न हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यह सिर्फ भ्रष्टाचारियों की करतूत है कि आम जनता को विकास से वंचित रहना पड़ता है।

सवाल यह उठता यह उठता है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। सरकार ने तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए विशेष विभाग तक बना डाले हैं। बार-बार यह कोशिश की जाती है कि भ्रष्टाचारियों की धर-पकड़ हो। कभी-कभी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ भी लिया जाता है और उसे इस अपराध के लिए जेल की सजा भी दी जाती है। पर क्या करें, भ्रष्टाचार लोगों की रग-रग में समा गया है। इतना बढ़ गया है भ्रष्टचार कि लोग़ इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि बिना रिश्वत दिये ही उनका काम हो सकता है। भ्रष्टाचार एक आदत का रूप ले चुका है। इस तरह सबको एक ही डंडे से हांक दिया जाता है। सभी लोग़ों को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या भ्रष्टाचार फैलाने के लिये आम लोग़ जिम्मेवार हैं या कोई अन्य? भारत में 70 प्रतिशत आबादी किसान और मज़दूरों की है। बाकी में छोटे-बड़े व्यवसायी, अफ़सर और राजनीतिक नेता आ जाते हैं। यानी शासक वर्ग के लोग़। यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि देश की बहुलांश आबादी जो किसान है, खेतों में काम करती हुई किस तरह का और कैसे भ्रष्टाचार करती है?

कुल मिला कर इस देश के लोग़ों का भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इस बात की कोई को कोशिश नहीं की जाती कि भ्रष्टाचारियों की अलग से कोई पहचान की जाये। आखिर भ्रष्टाचार के लिए कौन से लोग़ पूरी तरह जिम्मेवार हैं? यहां तो साफ़ यह कह भिश्आचारियों और भ्रष्टाचारियों को कारण ही यहां सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग़ों में कौन हैं? यहां तो स्पष्ट कह दिया जाता है कि सरकार क्या करे? भ्रष्टाचारियों के कारण वह तबाह है। भ्रष्टाचारी उसकी एक नहीं चलने देते। अन्यथा उसकी पूरी कोशिश है कि लोग़ों का विकास का फल मिले। विकास सिर्फ़ हो ही नहीं, बल्कि लोग़ों को दिखाई भी पड़े। यहां के लोग़ों को भ्रष्टाचार की ऐसी छुतहा बीमारी लग गई है कि समझ में नहीं आता कि इस पर रोक लगाने के लिये क्या किया जाये। यानी सरकार जो कदम उठा रही है, सब ठीक है। एक ही अड़चन है और वह है भ्रष्टाचार।

यहां सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। सरकार ने तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए विशेष विभाग तक बना डाले हैं। बार-बार यह कोशिश की जाती है कि भ्रष्टाचारियों की धर-पकड़ हो। कभी-कभी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ भी लिया जाता है और उसे इस अपराध के लिए जेल की सजा भी दी जाती है। पर क्या करें, भ्रष्टाचार लोग़ों की रग-रग में समा गया है। इतना बढ़ गया है भ्रष्टचार कि लोग़ इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि बिना रिश्वत दिये ही उनका काम हो सकता है। भ्रष्टाचार एक आदत का रूप ले चुका है।

इस तरह सबको एक ही डंडे से हांक दिया जाता है। सभी लोग़ों को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या भ्रष्टाचार फैलाने के लिये आम लोग़ जिम्मेवार हैं या कोई अन्य? भारत में 70 प्रतिशत आबादी किसान और मज़दूरों की है। बाकी में छोटे-बड़े व्यवसायी, अफ़सर और राजनीतिक नेता आ जाते हैं। यानी शासक वर्ग के लोग़। यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि देश की बहुलांश आबादी जो किसान है, खेतों में काम करती हुई किस तरह का और कैसे भ्रष्टाचार करती है? और मज़दूर जो खेतों और फैक्टरियों में काम करते हैं, कैसे कोई भ्रष्टाचार करते हैं? फिर भ्रष्टाचार में कौन संलग्न है? क्या नेताओं और अफसरों की मुट्ठी भर आबादी? निश्चय ही।

जब किसान और मजदूर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते तो भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से नेता और अफ़सर जिम्मेदार हैं। यही वह वर्ग है जो दिन-रात भ्रष्टाचार में लगा हुआ है इसके नित नये अवसर पैदा कर रही है वर्तमान व्यवस्था जो मज़दूरों और किसानों के शोषण पर आधारित है। इस व्यवस्था में कोई अफ़सर और नेता यदि वास्तव में ईमानदार भी हो तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो सकता, बल्कि इस भ्रष्ट व्यवस्था में उसका दम घुट सकता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में कोई व्यक्ति सिर्फ सदिच्छा से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार को जन्म देने, उसे पालने और पोसने में वर्तमान व्यवस्था और उसे संचालित करने वाले लोग लगे हुए हैं। इस व्यवस्था में ईमानदार लोग़ों को धक्का दे कर तुरंत किनारे कर दिया जाता है।

- गरीब दास